



वास्तविक स्वामित्व की पहचान

किसी कंपनी या ट्रस्ट के वास्तविक स्वामित्व की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी विभिन्न देशों की सरकारों के बीच सहयोग और तालमेल जरूरी है। इस दिशा में पहला कदम यही हो सकता है कि कंपनी या ट्रस्ट के वास्तविक मालिक की पहचान सुनिश्चित करने का आसान तरीका निकाला जाए।

नवीन सिंह।

इंटरनेशनल कन्सॉर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) द्वारा सामने लाए गए एक करोड़ बीस लाख दस्तावेज का नया सेट जिसे पैडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है, बताता है कि कैसे दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोग अपनी संपत्ति छुपाने और बढ़ाने के लिए टैक्स हेवंस में ऑफशोर कंपनियों और ट्रस्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के उपाय अपनाने वाले सभी लोग अनिवार्य तौर पर दुर्भावना या टैक्स चोरी की नीयत से प्रेरित नहीं कहे जा सकते, लेकिन कुछ लोग निश्चित रूप से इस श्रेणी में आते हैं। चूंकि पैडोरा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए हैं, उनमें भारत के भी कई जाने माने लोग हैं

इसलिए इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अच्छी बात है कि सरकार ने देर किए बगैर इनकी कई एजेंसियों से जांच के आदेश दे दिए हैं। मगर इस मामले में व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बगैर दोस कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। किसी कंपनी या ट्रस्ट के वास्तविक स्वामित्व की पहचान सुनिश्चित करने के लिए भी विभिन्न देशों की सरकारों के बीच सहयोग और तालमेल जरूरी है। और, कहने की जरूरत नहीं कि इस दिशा में पहला कदम यही हो सकता है कि कंपनी या ट्रस्ट के वास्तविक मालिक की पहचान सुनिश्चित करने का आसान तरीका निकाला जाए।

हर फाइनेंशियल सिक्योरिटी होल्डर (चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई अन्य लीगल एंटीटी) का अपना एक खास आइडेंटिफायर

होना चाहिए ताकि कंपनियों और ट्रस्टों के जाल के पीछे होने पर भी उस अल्टिमेट बेंचमार्क तक पहुंचा जा सके। भारत में कॉमन डायरेक्टर

आइडेंटिफिकेशन नंबर देने की व्यवस्था को इस लिहाज से सही दिशा में उठाया गया कदम माना जा सकता है। आरबीआई लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर भी ऐसा ही कदम है। लेकिन ये कदम तब नाकाफी साबित होते हैं जब उपलब्ध साक्ष्य किसी टैक्स हेवन की किसी अस्पष्ट सी पहचान की ओर इशारा करते हैं। इसलिए वक्त आ गया है जब जी-20 को तमाम टैक्स हेवंस के लिए कोई समय सीमा तय कर देनी चाहिए। उन्हें लीगल ओनर्स से जुड़ी सभी सूचनाएं इसलिए भी मुहैया करानी

हैं ताकि 15 फीसदी ग्लोबल मिनिमम टैक्स से जुड़े समझौते पर अमल हो सके। इस समझौते का भी मकसद टैक्स हेवंस खत्म करना ही है। बहरहाल, मौजूदा मामले का जहां तक सवाल है तो यह याद रखने की बात है कि कई कंपनियां सर्वथा वैध मकसद से ऑफशोर एंटीटी बनाती और संचालित करती हैं। इसलिए यह धारणा बना लेना उचित नहीं होगा कि ऑफशोर रजिस्टर्ड ट्रस्ट से जुड़े सारे लोग गलत ही हैं। दूसरी बात यह कि जांच शुरू कर देने के बाद उसे अनंत काल तक जारी रखना भी ठीक नहीं। यह अपने आप में एक यातना हो जाती है। एक उपयुक्त समय के अंदर जांच पूरी करके या तो प्रॉसिक्यूशन शुरू कर देना चाहिए या फिर साक्ष्य न मिलने की स्थिति में फाइल क्लोज हो जाना चाहिए।



आशा

अशोक बोहरा।
कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे

धर्म-दर्शन



दिए। बाद में कंजूस को एक कब्र में लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। बस एक छोटा से छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात हुई। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर कब्र में लेटे कंजूस की घबराहट का ठिकाना न रहा। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो उस छेद में बादाम के छिलके आड़ बनकर आ गए।

संपादकीय

पैरों पर कुल्हाड़ी

वाराणसी, अयोध्या, विंध्याचल, प्रयागराज और दूसरे धार्मिक-सांस्कृतिक रूप से प्रमुख स्थलों पर बीजेपी को घेरना विपक्ष के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, सुरक्षा और आतंकवाद तथा जम्मू-कश्मीर आदि मुद्दों पर बीजेपी को जितना घेरते हैं, उसके लिए चुनाव अभियान उतना ही आसान होता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष में यह धारणा बनी कि ममता बनर्जी ने स्वयं को निष्ठावान हिंदू साबित किया और इसका असर मतदाताओं पर पड़ा। यहां केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि बंगाल का चुनावी माहौल, सामाजिक-धार्मिक समीकरण अलग था। करीब 30 प्रतिशत मुस्लिम वोट और बड़े पैमाने पर वामपंथी सोच के मतदाताओं के रहते बीजेपी के लिए तृणमूल को पराजित करना आसान नहीं था। उनके सामने बीजेपी को हराना ही एकमात्र लक्ष्य था और विकल्प तृणमूल ही थी। ऐसा अन्य राज्यों में नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं। पिछले चुनाव में भी अखिलेश ने अंकोरवाट की तर्ज पर विष्णु मंदिर बनाने की घोषणा कर दी थी। मतदाता उस समय प्रभावित नहीं हुए तो आज कैसे हो जाएंगे? कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष बीजेपी के खिलाफ एकजुट तो नहीं ही है, ठीक से अपने मुद्दे भी नहीं चुन पा रहा। वह थोड़ी सी बुद्धि खर्च करे तो बीजेपी और सरकार के विरुद्ध ऐसे मुद्दे मिल सकते हैं, जिन पर उसे रक्षात्मक बनाया जा सकता है। वरना यही हाल रहा तो बहुत संभव है कि विपक्षी दलों का अभियान ही अगले चुनावों में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दे।

यह समझ से परे है कि जिस जिन्ना को आम भारतीय खलनायक के रूप में देखता है, उसका इन महापुरुषों के साथ नाम लेने की क्या आवश्यकता थी।

विभाजन के खलनायक

अवधेश कुमार।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर नजर दौड़ाए तो बीजेपी अपने मुद्दों के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती दिखती है, लेकिन ज्यादा दिलचस्प यह है कि विपक्षी दल भी ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जो बीजेपी के लिए ज्यादा अनुकूल हैं। ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को खड़ा किए जाने का है। उन्होंने कहा कि ये सभी एक ही संस्थान से पड़े, बैरिस्टर बने और आजादी के संघर्ष में भाग लिया। यह समझ से परे है कि जिस जिन्ना को आम भारतीय खलनायक के रूप में देखता है, उसका इन महापुरुषों के साथ नाम लेने की क्या आवश्यकता थी।

वैसे, उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनावी समीकरणों के मद्देनजर मुसलमानों का बड़ा समूह अगर बीजेपी के विरुद्ध रणनीतिक मतदान करेगा तो संभवतः उसकी पहली पसंद एसपी ही होगी। अखिलेश इसे पक्का करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन बहुसंख्य मुसलमान जिन्ना को अपना महापुरुष मानकर वोट देंगे, यह मानना कठिन है। जिन्ना भारत विभाजन के सबसे बड़े खलनायक थे। एक समय भले वह अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में



शामिल थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाया, विभाजनकारी वक्तव्य दिए और 'डायरेक्ट एक्शन' के जरिए दंगे कराए।

विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले ऐसे मुद्दे बीजेपी के लिए मुंहमांगा वरदान साबित होते हैं। तय मानिए कि बीजेपी किसी न किसी रूप में जिन्ना का नाम पूरे चुनाव तक जिंदा रखेगी। अखिलेश ने बिन मांगे बीजेपी की तरफ से जिन्ना नाम का एक घातक तीर दे दिया है। अब अखिलेश बीजेपी और योगी सरकार के विरुद्ध जो भी मामले उठाएं, बीजेपी के लिए यह कह कर जवाब टाल देना आसान हो गया

है कि भाई, उन्हें तो जिन्ना चाहिए।

यह कोई पहली घटना नहीं है। यूपी की विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी को ऐसे मुद्दे दे रही हैं या वे स्वयं बीजेपी के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण संघ परिवार और बीजेपी के अजेंडे में रहा है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार ने निर्माण में तेजी लाई और अब व्यवस्थित तरीके से यह कार्य आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर किसी और पार्टी के नेता चुनाव पूर्व अयोध्या की यात्रा करते हैं और कहते हैं कि वे परम भक्त हैं तो बीजेपी उसे किस रूप में भुनाएगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। एसपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों पर बीजेपी नेता यह कहते हुए हमला करते हैं कि ये चुनावी राम भक्त हैं। इन्होंने हमेशा राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध किया। कोई नेता अयोध्या जाए, राम का दर्शन करे, स्वयं को निष्ठावान हिंदू कहे, इसमें समस्या नहीं है, लेकिन चुनावी दृष्टि से देखें तो इस पायदान पर बीजेपी सबसे ऊंचाई पर दिखाई देती है।

आखिर मंदिर निर्माण का फैसला आने से पहले ही योगी सरकार ने अयोध्या के पुनर्निर्माण की योजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया था। अयोध्या में दीपोत्सव महिमांडित त्योहार के रूप में स्थापित किया गया।

अष्टयोग-5048									
3			1		5				
7	30		25	2	34				
4		1		6		2			
	28	5	35		39				
	2	4		7					
5	30	3	42		34	7			
			6		2	1			

अपना ब्लॉग

धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात करने की कोशिश मोहन। धीरे-धीरे वाराणसी के समान अयोध्या को प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात करने की कोशिश हुई और उसमें काफी हद तक सफलता मिली। ऐसे में विपक्ष भला कैसे बाजी मार सकता है? जब विपक्षी नेता राम मंदिर को मुद्दा बनाते हुए कहते हैं कि वे ही असली रामभक्त हैं तो उनके पास अपना किया दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, जबकि बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। बीएसपी के सतीश मिश्र के साथ भी यही बात है। बीजेपी याद दिला रही है कि कांशीराम, मायावती और बीएसपी हिंदू देवी-देवताओं के बारे में कैसे बातें करते रहे हैं। मायावती के लिए बीएसपी के सिद्धांतों के कायम रहते हुए अयोध्या जाकर राम मंदिर में माथा टेकना आसान नहीं है। यह भी गौर करने लायक है कि हर पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है। ब्राह्मण केवल एक सामान्य जाति नहीं धार्मिक रूप से सबसे ज्यादा आस्थावान और कर्मकांड कराने वाला ऐसा समुदाय है, जो धार्मिक स्थलों व प्रतीकों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। आप ब्राह्मणों के बीच जाकर उनके मुद्दे उठाएंगे तो बीजेपी भी अपने कामों को सामने रखेगी और फिर दोनों में तुलना होगी।

जौकरी मांगने वालों पर लट्ट बजाए के आदेश है।

